उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

21 मार्च, 2018 • वर्ष 1, अंक 9

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 'एक साल नई मिसाल' कार्यक्रम में
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी तथा केशव प्रसाद मौर्य जी

- भ्रष्टाचार रोकेगा 'एंटी करप्शन पोर्टल'
- चार लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार
- गरीबों को मिलेगा उनके आवास का पट्टा
- मिट्टी हुई रायल्टी मुक्त, सस्ती होंगी ईंटें
- गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति कुंतल तय
- गंगा के किनारों पर फैलेगी हरियाली

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

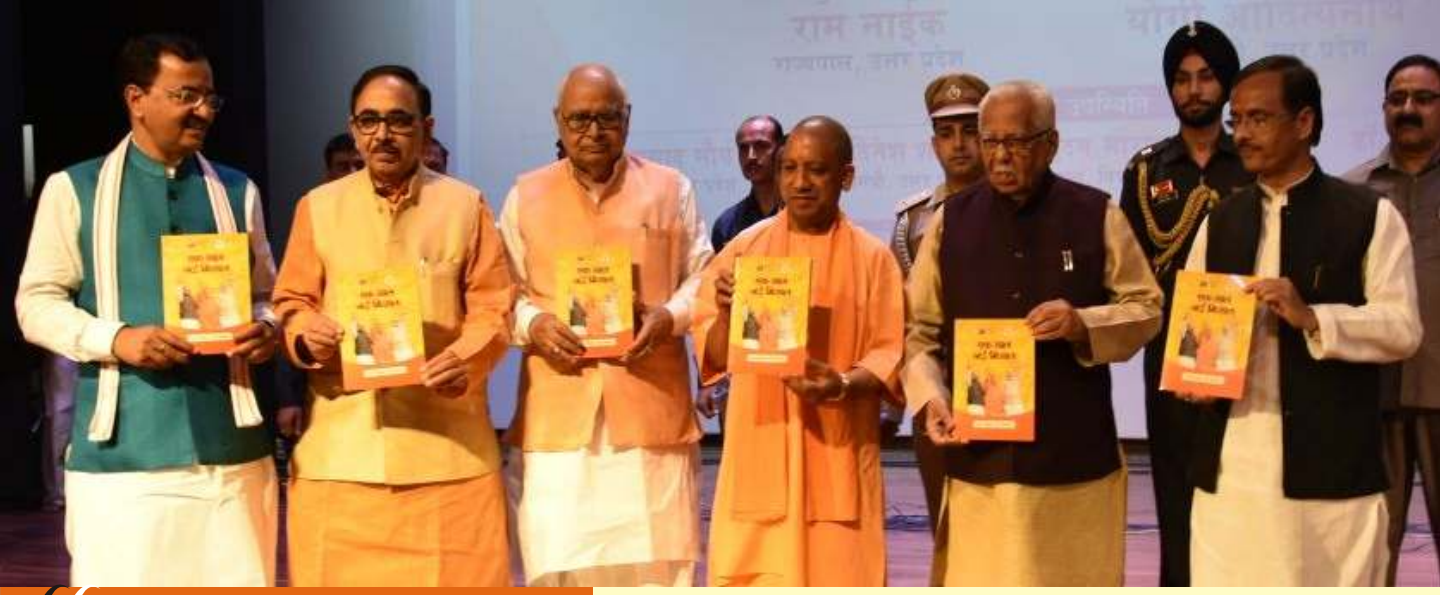

एक साल नई मिसाल

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर भरोसा करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ओजस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च, 2017 को शपथ ली थी।

वर्तमान सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठाते हुए विगत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश का नवोत्कर्ष हुआ है। विकास को नई गति मिली है और लोगों को सुरक्षा की गारण्टी। बदले हुए वातावरण में प्रदेश अब विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है।

लोक कल्याण के प्रति समर्पित राज्य सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को चाक-चौबन्द रखने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर सजग है।

प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने लगातार इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का गम्भीरता से कार्य कर रही है।

प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पिछले साल में सकारात्मक निर्णय लिये हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा और गति मिली है।

विशाल आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने लोक भवन में प्रदेश सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर आयोजित 'एक साल नई मिसाल' कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विशाल आबादी वाला राज्य है। ऐसे में उसके विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का भलीभांति निर्वाह किया है।

औद्योगिक निवेश के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश

राज्यपाल महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने उनकी सलाह पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने पर सहमति जतायी, जिससे अब यह आयोजन हर वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में विगत फरवरी माह में उ.प्र. इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन कर यह संदेश दे दिया कि राज्य अब औद्योगिक निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का उत्तम प्रदेश बन जाएगा।

एक वर्ष के अन्दर प्रदेश में राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए, प्रदेश का वातावरण कैसे बदला, यू0पी0 के परसेप्शन को बदलने में कितनी सफलता प्राप्त हुई, उसे पिछली 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में सम्पन्न उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट ने साबित करके दिखाया है। इन्वेस्टर्स समिट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, जब देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और निवेशकों ने लखनऊ पहुंचकर यह स्पष्ट कर दिया कि वे यूपी में क्यों आना चाहते हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों और केन्द्र सरकार के सहयोग से यह आयोजन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहा।

परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तीकरण का एक वर्ष

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च, 2017 को शपथ ली थी। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल का सफलतम एक वर्ष पूरा कर लिया है। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 01 वर्ष की अवधि एक छोटा कार्यकाल है। सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी थी, लेकिन दृढ़ निश्चय के धनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मात्र एक वर्ष की अल्प अवधि में ही पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए हैं।

"प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सुशासन के माध्यम से 'सबका साथ, सबका विकास' करने का जो संकल्प लिया है, उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी जनता को जनार्दन मानकर उनकी सेवा कर रही है। राज्य सरकार अतीत के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लेकर, अतीत की बुराइयों का समय रहते परिमार्जन कर रही है। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है कि जब शासन की नीतियों और योजनाओं का आधार व्यक्ति, परिवार, जाति अथवा मजहब को न बनाकर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला सहित प्रदेश के दलित, वंचित और उपेक्षित वर्गों को बनाया गया है।

–योगी आदित्यनाथ

हर कदम किसानों का साथ

किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, किसानों द्वारा 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋण को 01 लाख रुपये की सीमा तक माफ किया गया। इसके लिए वर्ष 2017–18 के बजट में राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त 36 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था 86 लाख सीमान्त एवं लघु किसानों को राहत देने के उद्देश्य से की गई।

किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर

किसानों की आय को दोगुना करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च है। इसी दृष्टिकोण से सरकार ने एक साल के कार्यकाल में किसान ऋण मोचन, गेहूं क्रय तथा धान क्रय पर विशेष ध्यान दिया है। परिणामस्वरूप इस अवधि में गत वर्ष की तुलना में करीब 5 गुना अधिक गेहूं एवं करीब डेढ़ गुना अधिक धान का क्रय किया गया है।

किसानों को सीधे खातें में भुगतान

गेहूं क्रय में 08 लाख 646 किसानों को 6 हजार 11 करोड़ रुपये की धनराशि, धान क्रय में 04 लाख 92 हजार 906 किसानों को 6 हजार 663 करोड़ रुपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे प्रदान की गई है। गन्ना मूल्य भुगतान के रूप में करीब 20 लाख किसानों को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये की धनराशि, जिसमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपये वर्तमान गन्ना सीजन के पूर्व का है। किसानों को कुल लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है।

आलू विकास बोर्ड की होगी स्थापना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों के लिए आलू विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में दो सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर पोटैटो की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों पर आलू उत्पादकों को एक ही स्थान पर उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

भ्रष्टाचार रोकेगा 'एंटी करप्शन पोर्टल'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए 'एंटी करप्शन पोर्टल' लांच किया है । इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार संबंधी आडियो अथवा वीडियो अपलोड कर सकता है। प्राप्त शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी। इस प्रक्रिया में शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी। सरकार के इस कदम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी को ताकतवर बनाने में सहायता मिलेगी।

पंजीकरण के बाद दर्ज होगी शिकायत

जनसुनवाई पोर्टल पर ही एंटी करप्शन पोर्टल मिलेगा। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत करने के लिए शिकायतकर्ता को इसमें पंजीकरण कराकर अपना मोबाइल नंबर तथा ई–मेलआईडी देनी होगी। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी पहचान गुप्त रखने का भी विकल्प पोर्टल पर है। आवेदन में शिकायतकर्ता को अधिकारी/कर्मचारी का नाम, स्तर, विभाग तथा उस पर लगाए गए आरोप का विवरण भरना होगा। इसमें आडियो और वीडियो क्लिप अपलोड करने की भी सुविधा दी गई है। आवेदन सबमिट करने के बाद प्राप्त शिकायत पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी।

आम जन को सारी सरकारी सुविधाएं बिना दफ्तरों एवं अधिकारी/कर्मचारियों का चक्कर लगाए सुलभ कराने के लिए, सरकार ने समस्त शासकीय सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। निर्णय में पारदर्शिता एवं शीघ्रता की दृष्टिकोण से सचिवालय स्तर पर 22 विभागों में पहली बार 'ई–ऑफिस' प्रणाली लागू की गयी है। इसे विस्तारित करते हुए सचिवालय के सभी विभागों, सभी निदेशालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों तक वर्ष 2018 के अन्त तक ले जाया जाएगा।

चार लाख युवाओं को नौकरी देगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु गंभीर हैं। युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार इस वर्ष 64 विभागों में चार लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी।

प्रदेश में निवेश के रास्ते मिलेगा रोजगार

प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के अन्तर्गत जो एमओयू साइन हुए हैं, उन पर तत्परता से कार्यवाही की जा रही है, ताकि प्रदेश में नये उद्योग स्थापित हों और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हों। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े, उन्हें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। समिट में साइन हुए सभी निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने के पश्चात् प्रदेश के लगभग 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा।

हर विभाग में होंगी भर्तियाँ

इस वर्ष पुलिस विभाग में उपनिरीक्षकों के अतिरिक्त सिपाहियों की 1.62 लाख भर्तियाँ होंगी। बेसिक शिक्षा में 1.37 लाख, माध्यमिक शिक्षा में दस हजार तथा उच्च शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जायेगा। नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी, राजस्व लेखपालों के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी नौकरियाँ प्रदान की जायेंगी। सारी भर्तियाँ पारदर्शी ढंग से ज्यादा से ज्यादा पदों पर की जायेंगी।

गरीबों को मिलेगा उनके आवास का पट्टा

जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, उनसे कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी, परन्तु यदि किसी गरीब ने ऐसी जमीन पर कच्चा अथवा पक्का घर बना लिया है, तो उसे उजाड़ा नहीं जायेगा। वह जमीन संबंधित व्यक्ति को पट्टा कर दी जायेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गरीबों तथा वंचितों को उनके आशियाने का पट्टा मिलेगा।

मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे पट्टों की समीक्षा

ऐसे पट्टे स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरी पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए दिये जायेंगे। किस जिले में कितने गरीबों को पट्टे दिये गये, इसकी समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे।

जारी रहेगा एण्टी भू माफिया अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियों पर नकेल कसने और सरकारी जमीनों को उनके कब्जे से मुक्त कराने के लिए एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसने बेहतरीन कार्य करते हुए कई सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। अवैध कब्जे के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा और सभी सरकारी जमीनों को भू–माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराया जायेगा।

बेहतर हुई सूबे की कानून व्यवस्था

वर्तमान प्रदेश सरकार ने बेपटरी कानून–व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कानून–व्यवस्था का राज स्थापित करने का कार्य किया है। परिणामस्वरूप दुर्दान्त अपराधी एवं माफिया या तो जेलों में कैद हैं या प्रदेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गये हैं। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2017 में प्रदेश में डकैती के मामलों में 5.70 प्रतिशत, हत्या में 7.35 प्रतिशत, रोड होल्डअप में 100 प्रतिशत, फिरौती में 13.21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली हत्या में 16.41 प्रतिशत और आगजनी में 29.73 प्रतिशत की कमी आयी है।

शत–प्रतिशत मामलों में दर्ज हो रही एफआईआर

पुलिस को शत–प्रतिशत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं। पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफआईआर काउन्टर खोले गये हैं। महिलाओं के प्रति अपराध की शुरुआत में ही रोकथाम के लिए एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है। जनमानस में सुरक्षा की भावना स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं।

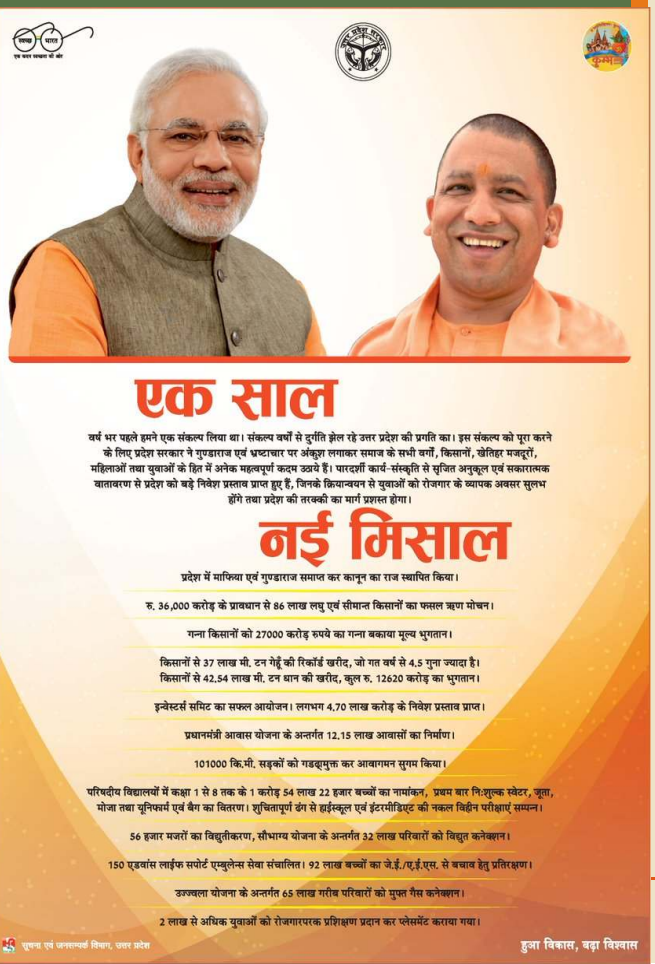

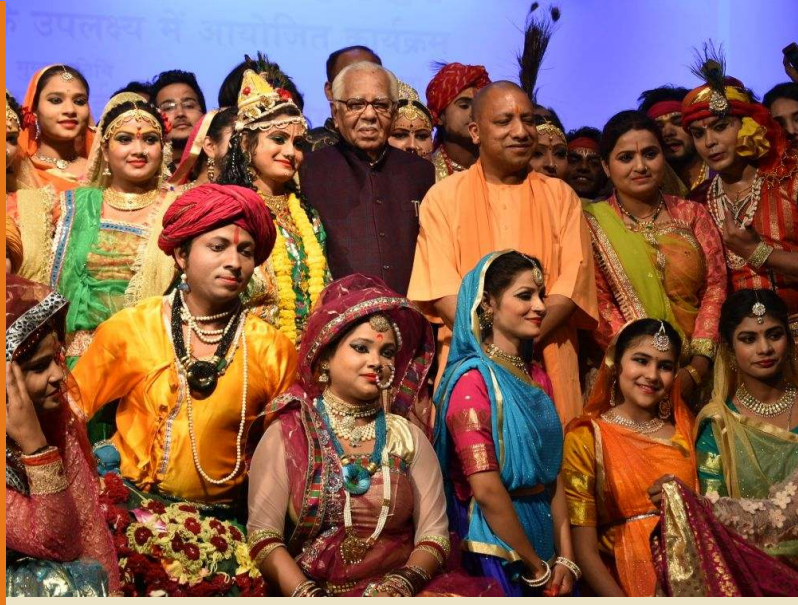

मिट्टी हुई रायल्टी मुक्त
सस्ती होंगी ईंटें

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मिट्टी को रायल्टी से मुक्त कर दिया है। अब मिट्टी ले जा रहे किसानों से न कोई शुल्क वसूला जाएगा और न ही कोई रायल्टी। नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी किसान कहीं से भी मिट्टी लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

अवैध चेकिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई सरकारी अधिकारी अथवा पुलिसकर्मी किसी मिट्टी ले जा रहे किसान की चेकिंग करेगा अथवा उसे परेशान करेगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी।

ईंट के दाम करने पर भट्टों की मिट्टी होगी रायल्टी फ्री

यदि ईट भट्टा व्यवसायी ईट के दाम कम करते हैं तो उनके भी मिट्टी रायल्टी मुक्त होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों को निर्माण कार्यो के लिए रायल्टी मुक्त मिट्टी मिलेगी।

सरकारी स्कूलों मे एक अप्रैल से एन.सी.ई.आर.टी. सिलेबस

शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु 1 अपैल से उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआटी की सिलेबस लागू किया जायेगा। सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि अधिकतम छात्र–छात्राएं इन सरकारी स्कूलों में शिक्षा हेतु आएं। इसी क्रम में सरकारी स्कूलों को कान्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

काशी की देव दीपावली का होगा भव्य आयोजन

प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार अयोध्या के दीपोत्सव और ब्रज के रंगोत्सव के बाद काशी की सुविख्यात देव दीपावली को और भव्य तरीके से आयोजित करेगी। कुंभ का इतिहास प्रदर्शित करने के लिए 'मल्टी मीडिया डिजिटल म्यूजियम' बनाया जायेगा, जिसमें देवासुर संग्राम से लेकर कुंभ तक का सारा इतिहास होगा। अयोध्या में प्रस्तावित रामकथा संग्रहालय में रामचरित मानस को जीवंत करने की तैयारी है।

“ राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है। अब सभी जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 57 हजार 26 मजरों को विद्युतीकृत करते हुए सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अन्तर्गत 32 लाख 77 हजार गरीब परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गये हैं।

–योगी आदित्यनाथ

ऐसा होगा सरकार का रोडमैप

25,000 करोड़ रूपये के एमओयू इसी माह होंगे क्रियान्वित

33,000 करोड़ रूपये से प्रारंभ होगा आगरा और कानपुर में मेट्रो का काम

सितम्बर 2018 तक शुरू होगी नोएडा–ग्रेटर नोएडा मेट्रो

1,500 करोड़ रूपये से 81 विकास खण्ड जुड़ेंगे 2–लेन सड़क से

1,000 करोड़ रूपये से 250 से अधिक आबादी वाली 1500 बस्तियां जुड़ेंगी सड़क से

1.75 करोड़ किसानों को मिलेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड

5,800 करोड़ रूपये से पनकी में बनेगा 660 मेगावॉट का पावर प्लांट

8,000 करोड़ रूपये से सुधरेगी प्रदेश की बिजली व्यवस्था

80 लाख निर्धन परिवारों को मिलेगा नि:शुल्क बिजली कनेक्शन

62,000 मजरों का होगा विद्युतीकरण

10 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा पक्का मकान

2,000 करोड़ रूपये से बुंदेलखाण्ड और विंध्य क्षेत्र में बेहतर होगी जल आपूर्ति

पीओएस मशीनों से जुड़ेंगी सभी राशन दुकानें, रूकेगी कालाबाजारी

हर जिले में बनेगी एक आदर्श नगर पंचायत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 16 मार्च 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये प्रति कुंतल तय

प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 1735 रूपये प्रति कुंतल की दर से 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने का निर्णय लिया है। यह खरीद 1 अप्रैल से 15 जून के मध्य की जायेगी। पिछले वर्ष सरकार ने गेहूँ किसानों को 1625 रूपये प्रति कुंतल की दर से भुगतान किया था, जिसमें इस वर्ष 110 रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

किसानों को 10 रूपये का बोनस भी मिलेगा

बढ़ी हुई दरों के अतिरिक्त गेहूँ किसानों को प्रति कुंतल 10 रूपये का बोनस भी प्रदान किया जायेगा। यह बोनस गेहूँ की छनाई व सफाई के लिए दिया जायेगा। इस वर्ष कुल 9 संस्थाएँ गेहूँ खरीदेंगी और 5500 गेहूँ क्रय केन्द्र बनाये जायेंगे। पिछले वर्ष 40 लाख मीट्रिक टन खरीद के सापेक्ष 36 लाख 99 हजार टन गेहूँ की खरीद हुई थी।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, समितियों और मिलों को पुरस्कार

प्रदेश की तीन–तीन चीनी मिलों, सहकारी गन्ना समितियों और किसानों को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत चीनों मिलों को स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा, जबकि सहकारी समितियों और किसानों को क्रमशः 51 हजार, 31 हजार व 21 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को 5 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस

प्रदेश सरकार ने मनोरंजन उद्योग में बड़ा बदलाव करते हुए सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स को 3 वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स के संचालन हेतु 5 वर्ष तक के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्रदान किये जायेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार अब सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स निर्माण पूरा होने के बाद डीएम के सम्मुख लाइसेंस का आवेदन किया जा सकेगा।

लखनऊ और अन्य शहरों में निजी कम्पनी करेगी बिजली वितरण कार्य

बिजली सेक्टर को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ तथा मुरादाबाद की विद्युत व्यवस्था निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया गया है। व्यवस्था हस्तांरण के उपरान्त बिजली कनेक्शन प्रदान करने से लेकर राजस्व वसूली तक का समस्त कार्य निजी कम्पनी फ्रेंचाइजी के तौर पर करेगी।

बिड के माध्यम से होगा कम्पनी का चयन

इस व्यवस्था को लागू करने वाले पाँचों शहरों में फ्रेंचाइजी तय करने के लिये बिड का आयोजन किया जायेगा। यह व्यवस्था लागू करने के बाद वित्तीय संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों में मजरों के विद्युतीकरण तथा विद्युत वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में प्रयोग किया जायेगा। इस व्यवस्था को लागू करने से लाइन हानियों में कमी, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की बेहतरी और उपभोक्ता सुविधाओं में सुधार का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

गंगा के किनारों पर फैलेगी हरियाली

गंगा की सफाई के साथ सरकार 'गंगा हरीतिमा अभियान' चलायेगी, जिसके अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे अवस्थित 27 जिलों में 21 मार्च से 16 सितम्बर 2018 तक नदी के दोनों तरफ एक किलोमीटर चौड़ाई में पौधरोपण किया जायेगा। इस अभियान में विशेषकर किसानों को 'एक व्यक्ति–एक वृक्ष' के माध्यम से प्रेरित कियो जायेगा। इस अभियान में साफ–सफाई, मृदा तथा जल संरक्षण तथा गंगा नदी के संरक्षण पर विशेष बल दिया जायेगा।

30 से 40 आयुवर्ग के अभ्यर्थी बन सकेंगे प्रधानाचार्य

327.14 करोड़ की लागत से बनेंगे 8 नये रेलवे ओवरब्रिज

पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए नई योजना

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 न्यायालय कक्ष, 20 चैंबर बनेंगे

पनकी में 660 मेगावाट की नई तापीय परियोजना को स्वीकृति

गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बनेगा आधुनिक बाल रोग चिकित्सालय

कैलाश मानसरोवर भवन के क्षेत्रफल और लागत वृद्धि स्वीकृत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 20 मार्च 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मिट्टी खनन में रायल्टी समाप्त

आम जनता को गृह निर्माण तथा विकास कार्यों में आ रही कठिनाइयों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने मिट्टी के खनन पर लगाई गई खनन रायल्टी समाप्त करने का निर्णय लिया है। अभी तक साधारण मिट्टी के खनन पर 30 रूपये प्रति घन मीटर की रायल्टी निर्धारित थी, जिसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।

पुलिस नहीं कर सकेगी मिट्टी खनन में हस्तक्षेप

पुलिस को मिट्टी खनन के मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा। मिट्टी खोदाई के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकार के इस निर्णय का लाभ मुख्यतः कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को मिलेगा, जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की खोदाई करते हैं।

मिट्टी पर रायल्टी समाप्त करने से सरकार की आय में कमी आएगी, परन्तु राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों की लागत में भी कमी आएगी।

परियोजनाओं की लागत होगी कम

प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण इकाईयों के अधिष्ठान व्यय के तौर पर मिलने वाली 3 प्रतिशत राशि को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया है। सरकार के इस निर्णय से परियोजनाओं के मुआवजे के आधे प्रतिशत के बराबर की कमी आएगी।

दो मेगा परियोजनाओं को मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की दो परियोजनाओं बुलंदशहर स्थित मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड तथा रायबरेली में रिलायंस सीमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा लेटर आफ कम्फर्ट की शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन के उपरान्त 206.36 करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जिस पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

सैनिक कल्याण निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया

कैबिनेट ने निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास की संविदा अवधि तीन वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष किये जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही वर्तमान निदेशक, सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर (अवकाश प्राप्त) अमूल्य मोहन की संविदा अवधि 12 सितंबर, 2018 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सरकारी राशन दुकानों में ही होगी केरोसीन की बिक्री

प्रदेश में मिट्टी का तेल अब सिर्फ सरकारी राशन दुकानों पर ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल की फुटकर बिक्री के लाइसेंस समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में केवल मिट्टी का तेल बेचने वाली लगभग 3900 दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से गरीबों को आसानी से सस्ता केरोसीन मिलेगा और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा।

लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं हेतु नियमावली मे संशोधन

वाराणसी में खुलने वाले केन्द्रीय विद्यालय के लिए हवाई पट्टी की 4.2 हेक्टेयर आरक्षित जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग को नि:शुल्क देने का निर्णय

वित्त विनियोग से सम्बन्धित 252 पुराने अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने का निर्णय

हथकरघा पुरस्कार योजना के प्रस्ताव पर होगा पुनर्विचार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक श्री अनुज कुमार झा द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी